

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

अष्टम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनाएँ झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्वर्गत दिनांक- 03.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य वर्ग बाज़	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	ठौ० सरफराज अहमद स०वि०स०	<p>बिहार पुनर्गठन अधिकारियम के तहत बिहार राज्य के लार्ज पट झारखण्ड में भी हर संवैधानिक एवं शैक्षणिक संस्थान, निगम, बोर्ड का गठन करने का प्रावधान है। विदित है कि हृकीर्ण वर्ष बीतने के बाद भी झारखण्ड राज्य में भद्रसा बोर्ड वकफ बोर्ड तथा उर्दू अकादमी का गठन नहीं किया गया है। फलस्वरूप अल्पसंख्यक समाज से जुड़ी समस्याओं का निराकरण रामुचित ढंग से जही हो रहा है। साथ ही भद्रसा तथा वकफ की जगील पर अतिक्रमण भी हो रहा है। अल्पसंख्यक समाज को राज्य सरकार से काफी उम्मीदें हैं।</p> <p>अतः राज्य में भद्रसा बोर्ड वकफ बोर्ड तथा उर्दू अकादमी का शीघ्र गठन करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का द्व्यान आकृष्ट करता हूँ।</p>	अनुसूचित जाति- जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण
02-	श्री भूषण बड़ा स०वि०स० श्री बंधु तिर्की स०वि०स० श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह स०वि०स०	<p>विदित हो कि सिजडेगा जिला में गृह रक्षा वाहिनिया की विस्थापित हेतु विज्ञापन सं०-०१/२०१६ के तहत गृह विभाग द्वारा ४४७ अभ्यर्थियों में से, ३६२ महिला/पुरुष अभ्यर्थियों का वर्ष २०१८ में चयन के लिये जाने के पश्चात् उक्त ३६२ सफल अभ्यर्थियों को बुनियादी प्रशिक्षण दिलाने का आदेश-</p>	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

01.	02.	03.	04.
		<p>विभाग ने अब तक पारित नहीं किया है जो अत्यंत ही शेष का विषय है। फलस्वरूप उक्त 362 ग्रह चर्यनित अभ्यर्थी वर्ष 2018 से बुनियादी प्रशिक्षण की आस में बेरोजगारी का दंश झेलने को विवश हैं।</p> <p>झात हो कि घरता, पाण्डुली, रामगढ़, लातेहार, सरायकेला, रौची जिला के अभ्यर्थियों को बुनियादी प्रशिक्षण दिलाने हेतु गृह विभाग के पारित आदेशबुसार वर्णित छे जिला में से लातेहार तथा रामगढ़ जिला के अभ्यर्थी बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पुल: झात हो कि उपायुक्त सिमडेगा छे पत्रांक- 269 दिनांक- 08.02.2020 संयुक्त सचिव, गृह विभाग, पुल: उपायुक्त सिमडेगा के पत्रांक- 1221 (II)/गो० मठानिदेशक सह- महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, शास्त्रखण्ड, रौची दिनांक- 25.09.2021 को सम्पूर्ण श्रुटियों को दुरुस्त करते हुए वर्णित 362 अभ्यर्थियों को बुनियादी प्रशिक्षण दिलाने का आगाह करने के बाद भी फलाफल अब तक शूल्य है जबकि उक्त 362 अभ्यर्थियों में से 290 अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के हैं, शेष अनुसूचित जाति/OBC के हैं, सिमडेगा उपायाद प्रभावित अत्यंत पिछड़ा एवं गरीब जिला है, बावजूद इसके 362 गृह रक्षा वाहिनियों को अब तक बुनियादी प्रशिक्षण नहीं दिलाना विचारणीय विषय है। साथ ही विभागीय कार्यशीली भी Right to Work के विलक्ष्य है।</p> <p>अतएव सिमडेगा जिला के नवचर्यनित 362 गरीब बेरोजगार गृह, रक्षा वाहिनियों को वर्णित 6 जिला के तर्ज पर चलते सब में बुनियादी प्रशिक्षण दिलाने हेतु गृह विभाग से आदेश पारित कर्याकर इन्हें भी बुनियादी प्रशिक्षण दिलाने हेतु सदन के माध्यम से सदन का द्याव आकृष्ट किया जाता है।</p>	

01.	02.	03.	04.
03-	श्री रामचन्द्र चन्द्रवर्षी स०वि०स० श्री नवीन जायसवाल स०वि०स०	<p>झारखण्ड सरकार ने दिनांक- 24.02.2022 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में निर्णय लिया है कि झारखण्ड में त्रिलोकीय पंचायत चुनाव शीघ्र कराया जाएगा, किन्तु यह भी निर्णय लिया है कि यह चुनाव पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किए बिना कराये जाएंगे। सरकार का यह निर्णय मानवीय उच्चतम व्यायालय के व्याय निर्णय के प्रतिकूल है जिसमें व्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि पिछड़े वर्गों का आरक्षण उसकी जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए। झारखण्ड में पिछड़े वर्गों की आबादी 56 प्रतिशत है, किन्तु उसे मात्र 14 प्रतिशत आरक्षण देय है जबकि राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति को उसकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद् का निर्णय मानवीय उच्चतम व्यायालय की भावना एवं आदेश के प्रतिकूल है।</p> <p>अतः मैं सरकार से मानवीय उच्चतम व्यायालय के आदेश के तहत राज्य में पिछड़े वर्गों को समूचित प्रावधान के तहत शीघ्र पंचायत चुनाव कराने की ओर व्याप्त आवृष्ट किया जाता है।</p>	पंचायती राज
04-	श्री विरंती नारायण स०वि०स०	<p>झारखण्ड में ई- निवायन पोर्टल की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन प्राप्त कर सकता था और अपनी संपत्ति का सेल-डीड ऑनलाइन निर्धारित शुल्क देकर सेल-डीड की सर्टफाईड कॉपी तत्काल प्राप्त कर सकता था।</p> <p>विगत जून 2021 से उक्त व्यवस्था को बंद कर दिया गया है और Public Access को रोक दिया गया है, जिससे एक साथ कई परेशानियाँ उत्पन्न हो गईं और कायम पारदर्शिता की व्यवस्था समाप्त हो गई है तथा बैंक से संपत्ति के विरुद्ध लोन लेने वाले लागों को फाफी</p>	राजस्व निवायन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		<p>परेशानी हो रही है, क्योंकि वैक लोन देने से पहले संपत्ति आभार प्रमाण-पत्र की मांग करता है, जो उक्त व्यवस्था के लागू रहने के कारण ऑनलाइन तरीके से छूटपट हो जाता था, लेकिन जून 2021 में उक्त व्यवस्था के बंद हो जाने के कारण राज्य के नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यह झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 का भी उल्लंघन है और उक्त व्यवस्था से हर वर्ष करीब 3 करोड़ लोगों का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो रहा था। वर्ष 2019 से 2021 के बीच निर्बंधित दस्तावेजों को एनजीडीआरएस के सर्व जोड़खूल से 10,30,406 बार ऑनलाइन सर्व किया गया है।</p> <p>उक्त व्यवस्था के बंद हो जाने के कारण राज्य में शू-आफिया सक्रिय हो गए हैं और जनीन दलालों के होसले बुलंद तुए हैं, क्योंकि अब राज्य के नागरिक अपनी जनीन की खारीद-बिक्री (निर्बंधन) पर अपनी ऑनलाइन बाजार नहीं रख सकते हैं, जबकि झारखण्ड ई-निर्बंधन के पोर्टल के सर्व-लिंक के कारण कोई भी नागरिक जनीन की खारीद-बिक्री से संबंधित निर्बंधित हीड को ऑनलाइन सर्व करके देख सकता था एवं वर्ष 1940 से लेकर वर्ष 2008 तक की झारखण्ड की सारी निर्बंधित हीड इस पोर्टल में ऑनलाइन अपलोड थी, जिससे पारदर्शी लोप से कोई भी नागरिक इनको देख सकता था, इनका अध्ययन कर सकता था और निर्धारित शुल्क देकर इनकी सार्टिफाईड कोपी प्राप्त कर सकता था, जिससे अष्टाघार पर भी अंकुश लगा था।</p> <p>अतएव सरकार का व्याज आकृष्ट कराते तुए मांग करता हूँ कि सरकार द्वाशीघ उक्त झारखण्ड ई-निर्बंधन के पोर्टल के सर्व-लिंक को ओपन करवाएं और-</p>	

01.	02.	03.	04.
		Public Access को सुनिश्चित करवाते हुए पारदर्शी शासन को कायम करे और अधिकारियों तथा भू-माफिया पर लगान लगाने हेतु व्यापक जलहित में पुनः पुरानी व्यवस्था लागू किये जाने हेतु सदन का ध्यानाकृष्ट करता है।	
05- श्री उमाशंकर अकेला स०विं०स०		हजारीबाग जिलान्तरगत बरही, चौपारण एवं चब्दवारा प्रखण्डों की हजारों एकड़ ऐतां की जमीन वर्ष- 1951-52 में D.V.C द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है और तिलैया जलाशय का निर्माण कराया गया। उक्त प्रखण्डों के लाखों परिवार विस्थापित परिवार हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन्हें जिन जमीनों पर बसाया गया है, यह अतियान में जंगल झाड़ व गैर मज़लआ अंकित है जिसके दुष्परिणाम स्वरूप इन किसानों के नाम से जमीन का रसीद जिर्गत नहीं हो रहा है। आज 70 वर्षों के दीतने के बाद भी ये किसान तंगहाली की जिन्दगी जीले को मजबूर है। अब इनकी जमीनों को NHAI द्वारा रोड चौड़ीकरण करने हेतु अधिग्रहित किया जा रहा है। इससे सम्पूर्ण क्षेत्र में हाहाकार मचा रुआ है और आगजन आक्रोशित है। अतः उक्त सम्पूर्ण नामलों की जाँच की मांग एवं किसानों के नाम से रसीद जिर्गत करने हेतु सदन का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।	राजस्थ निर्बंधन एवं भूमि सुधार

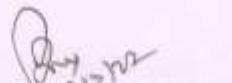
रौची,
दिनांक- 03 मार्च, 2022 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रौची।

-:: 6 ::-

आप सं०-प्र०ध्या०-०१/२०२२- ८४२ वि० स०, रौंची, दिनांक- ०२/०३/२०२२

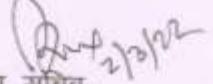
प्रति:- झारखण्ड विधान सभा के मार्गदर्शन/ मार्गमुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रौंची/ मानवीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, रौंची/ अबुसूधित जाति, अनुसूधित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/पंचायती राज विभाग एवं राजस्व नियंत्रण एवं भूमि सुधार विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

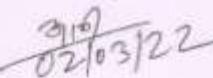

(एस० शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,

आप सं०-प्र०ध्या०-०१/२०२२- ९४२ वि० स०, रौंची, दिनांक- ०२/०३/२०२२

प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आपा सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सुभाष/-


उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रौंची।


०२/०३/२२